मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्षः 8 अंक 238
सोमवार, 16 मार्च 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल से शुरू होगा, बंगाल में 2 चरणों में होगा चुनाव, मतगणना 4 मई को होगी

नई दिल्ली, 15 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग (एउक) 15 मार्च (रविवार) को शाम 4:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अनुसार, मतदान 9 अप्रैल को शुरू होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव एक ही चरण में 9 अप्रैल को होंगे। तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। वहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे, जिसमें मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित है। आयोग ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने बताया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराने के लिए लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इन कर्मियों में मतदान कर्मचारी, सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे, जो चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को संभालने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव वाले पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2.19 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाएँगे। अधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं के लिए मतदान को सुलभ और सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। मतदान केंद्रों की यह बड़ी संख्या, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली इस चुनावी प्रक्रिया के विशाल पैमाने को दशार्ती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए, 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनावों को 20 से ज्यादा देशों के चुनाव आयोगों के प्रतिनिधि भी देखेंगे। इन प्रतिनिधियों को भारत में चुनावों के उत्सवपूर्ण, पारदर्शी और कुशल संचालन को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पाँच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के पैमाने के बारे में बताया, और इस पूरी प्रक्रिया को चुनावों का त्योहार कहा। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि इन चुनावों में 824 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिससे यह देश की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रियाओं में से एक बन जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी के लिए पहुँच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाएँगे। साथ ही, उन्होंने मतदाताओं की विविधतापूर्ण प्रोफाइल पर भी रोशनी डाली।

कुमार ने कहा, ₹आपको हमारे मतदाताओं की श्रेणियों का अंदाजा देने के लिए बता दूँ कि असम, केरल, यहाँ तक कि पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हमारे पास 100 साल से ज्यादा उम्र के, यानी शतायु मतदाता भी हैं। 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी-खासी है... कुल मिलाकर 2.18 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएँगे। इनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होंगे। हर मतदाता के लिए औसत संख्या 750 से 850 के बीच होगी, और किसी भी हाल में यह 900 से ज्यादा नहीं होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएँगे। कुछ पोलिंग स्टेशन खास तौर पर महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। सभी पोलिंग स्टेशनों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। और कुछ पोलिंग स्टेशन हमारे दिव्यांग भाई-बहनों द्वारा भी संचालित किए जाएँगे।

नेपाल में भारतीय तीर्थयात्रियों की बस गहरी खाई में गिरी, 7 श्रद्धालुओं की मौत व कई घायल

गोरखा, 15 मार्च। नेपाल के गोरखा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना में दो नेपाली नागरिक भी घायल हुए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब मनकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रही एक माइक्रोबस गोरखा जिले के सहिद लखन ग्रामीण नगरपालिका-3 के पास नियंत्रण खोकर सड़क से करीब 200 मीटर नीचे ढलान में गिर गई। गोरखा जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस अधीक्षक भारत बहादुर बीके के अनुसार माइक्रोबस में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों में पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं और सभी भारतीय नागरिक बताए गए हैं। दुर्घटना में घायल यात्रियों को चितवन के भरतपुर स्थित कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के उपनिदेशक सुदीप राज केसी के अनुसार नौ घायलों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मुथु कुमार (58), अनामालिक (58), मीनाक्षी (59), शिवगामी (53), विजयल (57), मीना (58) और तमिलारसी (60) के रूप में हुई है। वहीं घायलों में सोरानम (62), मंगदा जलम (65), सुभद्रा (75), मायाल (65), सरोजा (73), भाग्यलक्ष्मी (75) और मीनाक्षी (34) शामिल हैं, जिनका इलाज चितवन मेडिकल कॉलेज में जारी है। उन्होंने बताया कि तीन घायलों को न्यूरोसर्जरी आईसीयू में भर्ती किया गया है, जबकि दो अन्य का इलाज सर्जरी आईसीयू में किया जा रहा है। माइक्रोबस में मौजूद वाहन कर्मचारी संतोष गुरूंग ने बताया कि श्रद्धालु कुरिंतार (चितवन) से मनकामना मंदिर दर्शन के लिए गए थे।

दिल्ली शराब नीति मामला : हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली, 15 मार्च। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था। केजरीवाल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के फैसले को पलटने की मांग की है।

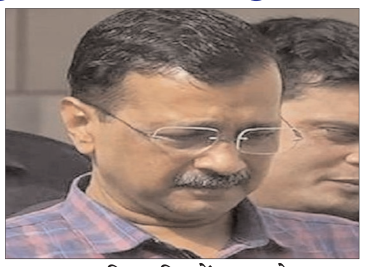

केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं ने एक पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। उन्होंने जस्टिस शर्मा के 9 मार्च के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उइक को अंतरिम राहत दी गई थी और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा के कुछ पिछले फैसलों की भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बेंच बदलने के केजरीवाल के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला मौजूदा रोस्टर के अनुसार जस्टिस शर्मा को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मामले से खुद को अलग करने का फैसला संबंधित न्यायाधीश को ही लेना चाहिए और उन्हें बदलाव के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला।

यह पूरा विवाद 27 फरवरी, 2026 को निचली अदालत के उस आदेश से शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ उइक ने हाई कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस शर्मा की बेंच कर रही है। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच बदलने की मांग की है और जस्टिस शर्मा के 9 मार्च के आदेश को भी चुनौती दी है।

मोदी विरोध के नाम पर भारत को बदनाम कर रही है कांग्रेसः अमित शाह

असम, 15 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के अपने दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी राजनीति के तौर-तरीकों पर जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के प्रयास में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। यह हमला दिल्ली में आयोजित अक इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन और संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी के आचरण को लेकर किया गया।

अमित शाह ने संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहाः संसद लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है। राहुल गांधी वहां सीढ़ियों पर बैठकर 'चाय-पकौड़े'

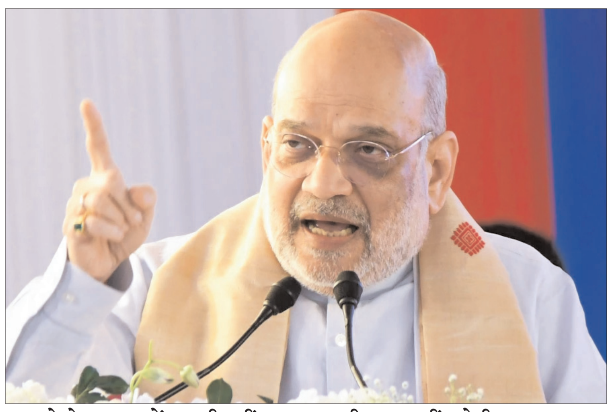

खा रहे थे। क्या उन्हें यह भी नहीं पता कि नाश्ता कहाँ करना चाहिए? हम भी कभी विपक्ष में थे, विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसके लिए एक सही मंच और मयार्दा होती है।

शाह ने आगे कहा कि अक समिट जैसे वैश्विक मंच पर बिना कपड़ों के प्रदर्शन करना सीधे तौर पर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश है, जिसे भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

स्वास्थ्य फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। कांग्रेस की आलोचना के साथ-साथ, शाह ने असम में पार्टी के पिछले शासन के रिकॉर्ड पर भी हमला बोला, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दशक पहले राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हालत में थी और दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने जन कल्याण के बजाय नेताओं के परिवारों की ₹आर्थिक सेहत₹ को ज्यादा प्राथमिकता दी।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि असम में सत्ता में रहने के 15 सालों के दौरान, कांग्रेस ने राज्य के स्वास्थ्य बजट से हर साल 150 करोड़ रुपये हड़प लिए। BJP को सुलभ चिकित्सा उपचार पर केंद्रित पार्टी के तौर पर पेश करते हुए, शाह ने कहा कि मौजूदा सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तारीफ की।

असम में बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू हुए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तारीफ करते हुए, शाह ने कहा कि असम स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा है और अब पड़ोसी क्षेत्रों के मरीजों के लिए एक उपचार केंद्र बनने की इच्छा रखता है।

उन्होंने कहा सीएम सरमा ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही असम को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। हिमंत आज कार में मुझे बता रहे थे कि वह असम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक भी मरीज को इलाज के लिए असम से बाहर न जाना पड़े। हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहाँ बंगाल और पूर्वोत्तर के गरीब मरीज इलाज करा सकें।

इस कार्यक्रम के दौरान, शाह ने गुवाहाटी में 675 करोड़ रुपये के प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (ढटउऌ) का उद्घाटन किया। उन्होंने असम कैंसर केयर फाउंडेशन (अउउ़ऋ) के तहत गोलाघाट और तिनसुकिया में दो कैंसर केंद्रों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया; इन दोनों केंद्रों को बनाने में 135 करोड़ रुपये की लागत आई है।

लेबनान में इजरायली हमलों से मौतों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 850 लोगों की जान गई

लेबनान, 15 मार्च। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच लेबनान में इजरायल के हमलों से हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ताजा हमलों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच गई है। लगातार हो रहे हमलों के कारण कई इलाकों में भारी तबाही और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हालिया हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है।

लगातार हवाई हमलों की वजह से लेबनान के कई रिहायशी इलाकों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों पर भी घायलों का दबाव बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात को लेकर चिंता जताई जा रही है और संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

अफगानिस्तान फिर कांपा 4.3 तीव्रता के भूकंप से धरती हिली

काबुल। अफगानिस्तान में रविवार को रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह जानकारी भारत के National Center for Seismology (NCS) ने दी। NCS के अनुसार यह भूकंप 155 किमी गहराई पर दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को भी अफगानिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था जिसकी गहराई 105 किलोमीटर थी। लगातार आ रहे इन झटकों ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप की गहराई तीन श्रेणियों में बांटी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अफगानिस्तान का Hindu Kush क्षेत्र भूकंपीय रूप से बेहद सक्रिय है।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

मेंस्ट्रुअल लीवः सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वैश्विक परिप्रेक्ष्य!

-सुनील कुमार महला

अहाल ही में, यानी कि 13 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल,भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात कही है कि इस तरह की नीति को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। वास्तव में इस क्रम में अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रकार का प्रावधान कानून के रूप में लागू किया गया, तो कई नियोक्ता महिलाओं को रोजगार देने से ही हिचक सकते हैं, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पेड पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका सुनने से ही इंकार कर दिया और इस मुद्दे पर व्यावहारिक चिंताओं को सामने रखा। यहां पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली शारीरिक परेशानियों को देखते हुए हर महीने कुछ दिनों का अवकाश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि गर्भावस्था के लिए तो अवकाश का प्रावधान किया गया है, लेकिन मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों के लिए कोई सार्वभौमिक व्यवस्था नहीं है। साथ ही, यह भी कहा गया कि कुछ राज्यों और कई निजी कंपनियों में महीने में दो दिन के 'पीरियड लीव' का प्रावधान किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को इसे नियम बनाने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने यह भी बताया कि केरल सरकार ने स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की है और देश की कई निजी कंपनियों में स्वेच्छा से 'पेड पीरियड लीव' दी जा रही है मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि कोई कंपनी अपनी इच्छा से पीरियड्स के दौरान छुट्टी दे रही है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही इसे कानून के रूप में सख्ती से लागू किया जाएगा, उसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना होगा। अदालत ने आशंका व्यक्त की कि ऐसा प्रावधान अनिवार्य होने पर संभव है कि नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बचने लगें। इससे महिलाओं को सरकारी नौकरियों, न्यायपालिका या अन्य पेशों में अवसर मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका करियर प्रभावित हो सकता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई बार ऐसी याचिकाएं एक तरह का डर पैदा करती हैं और यह संदेश देती हैं कि जैसे मासिक धर्म महिलाओं के साथ होने वाली कोई नकारात्मक या असाधारण घटना है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह कहा है कि महिलाओं को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि इस प्रकार की माँग कार्यस्थल पर महिलाओं के विकास और उनकी परिपक्वता को लेकर गलत मानसिकता भी पैदा कर सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता पहले ही अपनी मांग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष रख चुके हैं, इसलिए सरकार सभी हितधारकों से चर्चा कर इस विषय पर कोई नीति बनाने पर विचार कर सकती है। अदालत ने संबंधित प्राधिकरणों को यह सुझाव दिया कि वे इस अभ्यावेदन पर विचार करें और विभिन्न पक्षों से परामर्श करके नीति का प्रारूप तैयार करें। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी कहा कि विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन नियोक्ताओं के पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें पेड लीव देने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। वास्तव में, इस पूरे मुद्दे पर समाज और महिलाओं के बीच भी अलग-अलग मत सामने आए हैं। कई महिलाओं का मानना है कि उन्होंने दशकों के संघर्ष के बाद कार्यस्थल पर बराबरी का अधिकार प्राप्त किया है। ऐसे में विशेष अवकाश की अनिवार्यता उन्हें पुरुषों की तुलना में कमजोर या कम सक्षम दिखा सकती है। कॉर्पोरेट संस्कृति में अक्सर उपलब्धता को सफलता का पैमाना माना जाता है, इसलिए महीने में निश्चित छुट्टी लेने वाली महिला को महत्वपूर्ण परियोजनाओं या नेतृत्व की भूमिकाओं से बाहर रखा जा सकता है। कुछ महिलाओं का यह भी मानना है कि अनिवार्य पीरियड लीव के कारण कई संस्थान महिलाओं के बजाय पुरुषों को अधिक प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कई महिलाएँ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत भी कर रही हैं वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं का यह मानना है कि इस विषय में एक संतुलित या मध्य मार्ग होना चाहिए। उनके अनुसार 'पीरियड लीव' की अनिवार्य बनाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का विकल्प दिया जाना चाहिए। इससे महिला का काम भी प्रभावित नहीं होगा और उसे कार्यालय के तनावपूर्ण वातावरण से राहत भी मिल सकेगी। उनका यह भी मानना है कि इस प्रकार की व्यवस्था से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनकी पेशेवर गरिमा भी बनी रहेगी। दरअसल कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दर्द, ऐंठन, मतली और माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लगातार काम करना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए कुछ महिलाओं का कहना है कि पीरियड लीव का उद्देश्य भले ही नेक और संवेदनशील है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिससे महिलाओं की व्यावसायिक गरिमा और नौकरी की सुरक्षा पर कोई आंच न आए।बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि विश्व के कई देशों में पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं, हालांकि इसकी व्यवस्था हर देश में एक जैसी नहीं है। गौरतलब है कि कुछ देशों ने इसे श्रम कानून का हिस्सा बनाया है। जबकि कुछ स्थानों पर इसे कुछ कंपनियों या संस्थानों द्वारा अपनी इंटरनल पालिसी के रूप में लागू किया गया है।उदाहरण के लिए नाइके और भारत की कंपनी जौमेटो ने भी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव की नीति लागू की है। यहां यदि हम देशों की बात करें तो जापान में वर्ष 1947 से ही महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश लेने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी महिला कर्मचारी को पीरियड के दौरान काम करने में कठिनाई होती है, तो वह छुट्टी ले सकती है, हालांकि यह छुट्टी वेतन सहित होगी या नहीं, यह कंपनी की नीति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया में महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव का अधिकार प्राप्त है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के श्रम कानून में भी महिलाओं को मासिक धर्म के पहले दो दिनों में अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देश जांबिया में 'मदर्स डे लीव' के नाम से हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाती है, जिसके लिए चिकित्सकीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता भी नहीं होती। हाल के वर्षों में स्पेन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2023 में 'पेड पीरियड लीव' को कानूनी मान्यता प्रदान की, जिससे गंभीर मासिक धर्म पीड़ा से पीड़ित महिलाएं चिकित्सकीय सलाह के आधार पर अवकाश ले सकती हैं। बहरहाल, यहां कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर पीरियड लीव को लेकर एकरूपता नहीं है, लेकिन मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य और गरिमा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों और संस्थानों में इसके प्रति जागरूकता और नीतिगत पहल लगातार बढ़ रही है।

पंडित पर हंगामा या शब्दों की गलत समझ?

-सुरेश गांधी

यूपी एसआई भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न ने छेड़ी बहस : भाषा का वास्तविक अर्थ बनाम सामाजिक धारणाएं. क्या सचमुच गलत था सवाल या समझ की कमी ने खड़ा किया विवाद. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विकल्प ऐसे शब्दों से बनाए जाते हैं जो सही उत्तर से अर्थ की दृष्टि से मेल नहीं खाते, ताकि परीक्षार्थी सही शब्द पहचान सके। प्रश्न था अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द। इसका सही उत्तर स्पष्ट रूप से अवसरवादी है। इसलिए बाकी विकल्प ऐसे शब्द होते हैं जो उस अर्थ से बिल्कुल अलग हों। यहाँ पंडित शब्द का मूल अर्थ विद्वान, ज्ञानी है, जो अवसरवादी के अर्थ से बिल्कुल अलग है। इसलिए इसे एक सामान्य गलत विकल्प (डिस्ट्रैक्टर) के रूप में रखा जा सकता है। जहाँ तक दलित, ठाकुर, बनिया जैसे शब्दों का सवाल है, ये जाति/समुदाय सूचक शब्द हैं, जबकि पंडित शब्द का प्रयोग हिंदी में विद्वान या विशेषज्ञ के अर्थ में भी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आम तौर पर ऐसे जाति-सूचक शब्दों को विकल्प के रूप में रखने से बचा जाता है ताकि अनावश्यक सामाजिक विवाद न हो। मतलब साफ हैं सही उत्तर अवसरवादी है। पंडित का अर्थ विद्वान होने के कारण इसे एक सामान्य गलत विकल्प के रूप में रखा जा सकता है। जाति/समुदाय सूचक शब्दों को विकल्प में देना आम तौर पर परीक्षा की भाषा में उचित नहीं माना जाता। इसलिए किसी भी प्रश्न को देखने से पहले उसके भाषाई संदर्भ और परीक्षा की पद्धति दोनों को समझना जरूरी होता है

कभी-कभी एक छोटा-सा शब्द भी बड़ा विवाद खड़ा कर देता है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के हिंदी खंड में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर इन दिनों कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रश्न था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इसके विकल्पों में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी दिए गए थे। सामान्य हिंदी ज्ञान रखने वाला कोई भी परीक्षार्थी तुरंत समझ सकता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर अवसरवादी है। लेकिन विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल किए जाने पर कुछ समूहों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते यह एक भाषाई प्रश्न से बढ़कर सामाजिक बहस का विषय बन गया। यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सामने खड़ा करती है, क्या सचमुच प्रश्न में कोई गंभीर त्रुटि थी, या फिर यह विवाद भाषा की गलत समझ और भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है?

प्रतियोगी परीक्षाओं की पद्धति को समझना जरूरी

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की संरचना कैसे होती है। अधिकांश वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में एक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए जाते हैं। इनमें से केवल एक सही उत्तर होता है, जबकि बाकी विकल्पों को डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। इन गलत विकल्पों का उद्देश्य परीक्षार्थी की समझ को परखना होता है। यदि सभी विकल्प लगभग एक जैसे या सही प्रतीत हों, तो परीक्षार्थी के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती। इसलिए प्रश्नपत्र तैयार करते समय ऐसे शब्द भी विकल्पों में रखे जाते हैं जो स्पष्ट रूप से उस अर्थ से मेल नहीं खाते। इस संदर्भ में देखा जाए तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति हिंदी में अवसरवादीह्व कहलाता है। बाकी विकल्प :- पंडित, निष्कपट और सदाचारी, उस अर्थ से मेल नहीं खाते। इसलिए परीक्षा की तकनीकी दृष्टि से यह प्रश्न पूरी तरह सही और सामान्य माना जा सकता है।

पंडित शब्द का असली अर्थ क्या है?

विवाद का सबसे बड़ा कारण पंडित शब्द को लेकर बनी धारणा है। भारतीय भाषाई परंपरा में पंडित शब्द का मूल अर्थ विद्वान, ज्ञानी या किसी विषय का विशेषज्ञ होता है। संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में इस शब्द का प्रयोग लंबे समय से ज्ञान और विवेक के प्रतीक के रूप में होता रहा है। यही कारण है कि कई महान विद्वानों के नाम के साथ पंडित उपाधि जुड़ी हुई मिलती है। भारतीय शास्त्रों में भी पंडित शब्द का प्रयोग नैतिकता और विवेक के संदर्भ में हुआ है। एक प्रसिद्ध श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है,

मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत।

आत्मवत सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः।।

इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री को माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान तुच्छ और सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही सच्चा पंडित कहलाता है। यह परिभाषा बताती है कि भारतीय चिंतन में पंडित केवल पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उच्च चरित्र, संयम और नैतिक दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है।

ब्राह्मण और पंडितः दो अलग अवधारणाएँ

विवाद का एक कारण यह भी है कि कई लोग पंडित शब्द को सीधे ब्राह्मण जाति से जोड़कर देखते हैं। जबकि भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों शब्दों के अर्थ अलग हैं। ब्राह्मण पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से जुड़ा एक सामाजिक वर्ग हो सकता है, जबकि पंडित मूलतः विद्वता और ज्ञान का परिचायक है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ किसी व्यक्ति को उसके ज्ञान और विद्वता के कारण पंडित कहा गया, चाहे वह किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो पंडित शब्द को केवल जाति से जोड़ देना उसकी व्यापक सांस्कृतिक और भाषाई परंपरा को सीमित कर देता है।

फिर विवाद क्यों हुआ?

यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि प्रश्न तकनीकी रूप से सही है और पंडित शब्द का अर्थ विद्वान है, तो फिर विवाद क्यों हुआ। दरअसल आधुनिक समाज में कई शब्द ऐसे हैं जिनका मूल अर्थ कुछ और होता है, लेकिन समय के साथ उनकी सामाजिक धारणाएँ बदल जाती हैं। पंडित शब्द भी कुछ लोगों के लिए अब केवल एक जातिगत पहचान से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में जब यह शब्द किसी अलग संदर्भ में दिखाई देता है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक और सामाजिक समूह भी ऐसे मुद्दों को जल्दी से विवाद का रूप दे देते हैं, जिससे बहस और अधिक तीखी हो जाती है।

लोकतंत्र में सवाल उठाना भी अधिकार

यह भी उतना ही सच है कि लोकतांत्रिक समाज में किसी भी विषय पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है। यदि किसी समूह को किसी शब्द या संदर्भ से आपत्ति महसूस होती है तो वह अपनी बात रख सकता है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले भाषा, संदर्भ और तथ्य को समझा जाए। कई बार भावनात्मक प्रतिक्रिया तथ्यों से आगे निकल जाती है और अनावश्यक विवाद की स्थिति बन जाती है।

भाषा और समाज के बीच संतुलन

यह पूरा विवाद हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती; वह समाज, संस्कृति और इतिहास से गहराई से जुड़ी होती है। इसलिए परीक्षा संस्थाओं और प्रश्नपत्र तैयार करने वाली समितियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का चयन करते समय भाषाई शुद्धता के साथ-साथ सामाजिक संवेदनशीलता भी बनी रहे। वहीं दूसरी ओर समाज को भी यह समझना होगा कि किसी शब्द का अर्थ केवल उसकी वर्तमान धारणा से नहीं बल्कि उसके ऐतिहासिक और भाषाई संदर्भ से भी निर्धारित होता है।

विवाद से सीखने की जरूरत

यूपी एसआई परीक्षा के इस प्रश्न को लेकर पैदा हुआ विवाद शायद कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। लेकिन यह घटना हमें यह सोचने का अवसर जरूर देती है कि हम भाषा को किस तरह समझते हैं और उससे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ और परंपरा के साथ समझते हैं, या उन्हें केवल अपनी सामाजिक धारणाओं के चश्मे से देखते हैं? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर ही इस पूरे विवाद का वास्तविक समाधान भी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला व्यक्ति हिंदी में अवसरवादी ही कहलाता है और परीक्षा की दृष्टि से यही सही उत्तर है। पंडित शब्द का मूल अर्थ विद्वान और विवेकशील व्यक्ति है। यदि इसे केवल जाति के संदर्भ में सीमित करके देखा जाए तो यह भाषा की व्यापक परंपरा को संकुचित कर देता है। इसलिए इस पूरे प्रकरण को एक विवाद के रूप में देखने के बजाय इसे भाषा की समझ और सामाजिक दृष्टि के बीच संतुलन बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि अंततः शब्दों का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, न कि उसे अनावश्यक विवादों में उलझाना।

कटौती की मार कर्मचारियों पर, विधायकों के बढ़ते भत्ते

– डॉ. सत्यवान सौरभ

हाल के समय में सरकारी कर्मचारियों के बीच एक निर्णय को लेकर व्यापक चर्चा और असंतोष देखा जा रहा है। एलटीसी के बदले एक माह के वेतन के विकल्प को समाप्त करने का निर्णय कई कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अनेक कर्मचारी संगठनों और शिक्षकों ने इसे अपने हितों के विपरीत बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक है जो विभिन्न कारणों से यात्रा नहीं कर पाते थे और एलटीसी के बदले वेतन विकल्प का लाभ लेते थे।

यह मुद्दा केवल एक आर्थिक सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कर्मचारियों के मनोबल, उनकी आर्थिक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कर्मचारियों की परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय ले, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही नीतियों को धरातल पर लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। एलटीसी सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी समय-समय पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकें, अपने कार्य के दबाव से कुछ समय के लिए दूर होकर मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा हो सकें। इस सुविधा के माध्यम से कर्मचारियों को देश के विभिन्न हिस्सों को देखने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। हालांकि हर कर्मचारी के लिए यात्रा करना संभव नहीं होता। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे कर्मचारियों के लिए एलटीसी के बदले एक माह के वेतन का विकल्प एक व्यावहारिक समाधान था। यह विकल्प कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारे के रूप में कार्य करता था।

विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त राशि घर के खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा जरूरतों या अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती थी। ऐसे में जब इस विकल्प को समाप्त किया जाता है, तो इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है जो यात्रा नहीं कर पाते थे और इस विकल्प पर निर्भर रहते थे।

सरकारी कर्मचारियों की आय सामान्यतः निश्चित और सीमित होती है। उन्हें अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को उसी आय के भीतर संतुलित करना पड़ता है। यदि ऐसी किसी सुविधा को समाप्त किया जाता है, तो उसका प्रभाव सीधे उनके घरेलू बजट पर पड़ता है। यही कारण है कि इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों के बीच चिंता और असंतोष की भावना दिखाई दे रही है।

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता काफी हद तक कर्मचारियों के मनोबल पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी संतुष्ट और प्रेरित होंगे तो वे अपने कार्य को अधिक जिम्मेदारी और दक्षता के साथ करेंगे। लेकिन यदि उन्हें यह महसूस होने लगे कि उनकी सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही है, तो इससे उनके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विशेष रूप से शिक्षकों की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं। वे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, विचार और मूल्यों को आकार देने का कार्य करते हैं। इस दृष्टि से शिक्षकों की संतुष्टि और प्रेरणा समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यदि शिक्षकों और कर्मचारियों को यह महसूस हो कि उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो यह स्थिति लंबे समय में प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए कर्मचारियों से जुड़े निर्णयों में संवेदनशीलता और संतुलन का होना आवश्यक है। इस पूरे विषय के साथ एक और पहलू अक्सर चर्चा में आता है। आम जनता और कर्मचारियों के बीच यह धारणा भी बनती जा रही है कि जहाँ एक ओर कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विधायकों और जनप्रतिनिधियों के भत्तों तथा पेंशन में लगातार वृद्धि होती रहती है।

विधायक लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए उचित सुविधाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन जब तुलना की जाती है तो कर्मचारियों और आम जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या नीति निर्माण में संतुलन और समानता का ध्यान रखा जा रहा है। लोकतंत्र की मूल भावना यही है कि सभी वर्गों के साथ न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवहार किया जाए। यदि किसी वर्ग को यह महसूस हो कि उसके साथ असमान व्यवहार हो रहा है, तो इससे व्यवस्था के प्रति विश्वास कमजोर हो सकता है। सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की चुनौती भी होती है। कई बार आर्थिक परिस्थितियों के कारण खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका प्रभाव किसी एक वर्ग पर ही अधिक न पड़े। यदि किसी आर्थिक कारण से खर्चों में कमी करना आवश्यक हो, तो इसके लिए व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नीति निर्माण में पारदर्शिता और संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।

कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार होता है। यदि कर्मचारियों को यह विश्वास हो कि उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना जा रहा है, तो वे भी अपने कार्यों को अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ निभाते हैं।

संवाद के माध्यम से सरकार कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी भी सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक सीमाओं को समझ सकते हैं। इससे कई बार ऐसे समाधान निकल आते हैं जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य होते हैं।

वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि इस विषय को टकराव के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे संवाद और समझदारी के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाए। यदि आवश्यक हो तो सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है और ऐसा समाधान तलाश सकती है जिससे कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा हो और प्रशासनिक व्यवस्था भी संतुलित बनी रहे।

संभव है कि एलटीसी के बदले वेतन विकल्प को किसी संशोधित रूप में जारी रखा जाए या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के समाधान कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश दे सकते हैं और उनके मनोबल को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

किसी भी राज्य की प्रगति उसके कर्मचारियों की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारी ही वे लोग होते हैं जो सरकार की योजनाओं और नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।

इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

अंततः लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि हर वर्ग को यह महसूस हो कि उसके साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। यदि नीति निर्माण में समानता, संवेदनशीलता और संतुलन का ध्यान रखा जाए, तो न केवल कर्मचारियों का मनोबल मजबूत होगा बल्कि शासन व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनेगी।

ग्लोबल वार्मिंग नए तेवर में, धरती की उष्णता और तीव्रता से बढ़ेगी

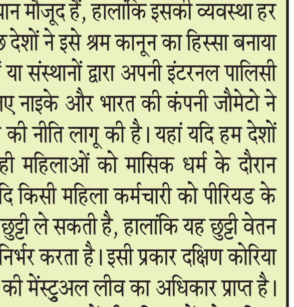

संजीव ठाकुर

ग्लोबल वार्मिंग या धरती की उष्णता की जब भी कहीं चर्चा होती है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिका,इंग्लैंड और तमाम यूरोपीय देश जिसमें फ्रां,इटली,कनाडा इजरायल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा पश्चिम एशिया के धनवान देश में इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा के कारण जहां वातानुकूलित मशीने, कल कारखाने, मोटर वाहन एवं अन्य ऐसी मशीने जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं दूषित हवा वायुमंडल में फैलती है ही बड़े जिम्मेदार होते हैं और इसका खामियाजा दक्षिण एशिया दक्षिण अफ्रीका और छोटे-छोटे देश को उठाना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के उपाय के लिए आयोजित बड़े-बड़े सम्मेलनों में यही बड़े देश अपनी जिम्मेदारी छोटे-छोटे देश पर डालकर निवृत्ति हो जाते हैं। जबकि सारा किया कराया इन्हीं देशों का होता है और छोटे-छोटे देश को इसके लिए नियमन पालन की जिम्मेदारी सौंप जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में ही जहां गरीबी ने अपना परचम फैला रखा है। शहरों में पेट्रोल ,डीजल, केरोसिन से चलने वाली गाड़ियों और वातानुकूलित यंत्रों याने ए,सी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने से वातावरण में उष्णता बढ़ते जा रही है' इसके अलावा वनों का विनाश एक भयानक समस्या के रूप में देश में फैलता जा रहा है' अंधाधुंध फैक्ट्रियों एवं मशीनों के उपकरणों से निकलने वाले धुंए से वातावरण विषैला बनाकर मनुष्य और जीव जंतुओं का जीना दूभर कर दिया है। वनों की कटाई के साथ-साथ कंक्रीट के जंगल धीरे-धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे हैं, ऐसे में शुद्ध वायु और और तापमान में आश्चर्यजनक बदलाव जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा ऋतु के परिवर्तन एवं बारिश में न्यूनता आने से धरती के तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी के चलते देश के कई शहरों में तापमान 48 से 50 सेल्सियस होने के कारण पशु पक्षी एवं मनुष्य की हीट स्ट्रोक से मृत्यु हुई हो जाती है। पानी की कमी तथा शरीर में डिहाइड्रेशन से लोगों की तथा वन्य पशुओं की लगातार मृत्यु हो रही है।

ग्लोबल वार्मिंग का खतरा वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया है और ऐतिहासिक तौर पर पिछले दो से तीन सौ वर्षों की तुलना की जाए तो बीते कुछ वर्षों में धरती का तापमान आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कुल मिलाकर 10 से 15 वर्ष ही शेष है। वैज्ञानिकों की यह बातें और रहस्योद्घाटन मानवता को डराने वाला जरूर है पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके उपायों की जो घोर अनदेखी की जा रही है वह अत्यंत चिंतनीय है। मानवता के लिए अत्यंत खतरनाक भी है। ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य के लिए खतरा है बल्कि जीव-जंतुओं समुद्र मैं पाए जाने वाले जीवो के लिए भी यह अत्यंत विषैला तथा खतरनाक हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जीवाश्म ईंधन के दशक ने एवं जलने से ग्लोबल वार्मिंग का तापमान तेजी से बढ़ा है एवं पूरी पृथ्वी जीवाश्म ईंधन के जलने से तेजी से धड़क रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी तथा दिए गए प्रमाण के बाद भी अनेक देश जो कार्बन उत्सर्जन के बड़े जिम्मेदार हैं, जीवाश्म ईंधन की इस्तेमाल को कम करने या खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत खत्म होने की बात तो दूर है कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और तो और इसके आसार भी निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों जिसमें अमेरिका ब्रिटेन के अलावा 32 देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन एवं जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं, सम्मेलन कर इस पर चिंता जरूर जताई है पर इसमें स्पष्ट तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन ,जापान चीन ,रूस की दादागिरी दिखाई देती है,यह छोटे गरीब देशों पर सारी जिम्मेदारी लादने का काम कर रहे हैं ।विश्व के कुल देशों में से लगभग 50 देश ऐसे हैं जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर पृथ्वी को धधकाने के कार्य का 60% तक हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन इन देशों को ग्लोबल वार्मिंग की चिंता की बजाए विकासशील देश एवं गरीब देशों पर पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दोषारोपण कर के अपनी इतिश्री कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण चिंतन जितने भी सम्मेलन हुए हैं इसमें बड़े देशों की नीति एवं दादागिरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चीन जो सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक देश है उसने पर्यावरण पर हुए सम्मेलनों में हिस्सेदारी तो दूर उसकी तरफ ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने चेतावनी दी है कि धरती के तापमान की वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43% से 50% तक कटौती करनी होगी। 2010 से लेकर 2021 तक दुनिया का औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मानव इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जो सर्वाधिक खतरे के निशान से भी ऊपर है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन के वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने उत्सर्जन को लगभग शून्य पर लाना होगा, और इस कार्य के लिए पूरी दुनिया को ऊर्जा क्षेत्र में बड़े और कार्यकारी बदलाव लाने होंगे, इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के उपभोग में भारी कमी भी लानी पड़ेगी। विगत 3 वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों में जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा साथी स्टोरेज बैटरी की लागत में आश्चर्यजनक गिरावट आई है जो लगभग गैस तथा कोयले की कीमत के बराबर हो गए हैं। कार्बन उत्सर्जन अभी 54% अधिक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो दुनिया के सब अमीर देश अकेले विश्व के कुल गैस उत्सर्जन के लिए बड़े जिम्मेदार पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले आठ दस सालों में अपने गैस उत्सर्जन में कटौती को आधा यानी 50% से कम नहीं करती है तो वर्ष 2050 तक उसे शून्य स्तर पर लाना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मोटे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के कुल वैश्विक उत्सर्जन में सहित 6.8 प्रतिशत का हिस्सेदार है। 1990 से लेकर 1920 तक भारत के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक में 175% की बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 2021 के बीच देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की मात्रा 17 फीसदी बढ़ी है, राहत की बात यह है कि अब भी भारत का उत्सर्जन स्तर जी-20 देशों के औसत स्तर से बहुत नीचे है। देश में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 11% की है, भारत की कुल ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन आधारित प्लांट का योगदान 74% है। यदि कार्बन उत्सर्जन को रोका नहीं गया और जीवाश्म ईंधन के उपयोग की रफ्तार यही रही तो भारत सहित विश्व के अधिकांश देश अपनी धरती को बचाने में सक्षम नहीं होंगे।

तलासरी में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर संपन्न

पालघर(उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र शासन के महसूल विभाग द्वारा चलाए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर अभियान (चरण-1) के अंतर्गत शनिवार को तहसील कार्यालय, तलासरी में राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और उन्हें विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विधायक विनोद निकोले मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगराध्यक्ष सुरेश भोये, उपनगराध्यक्ष सुभाष दुमडा, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सूत्रसंचालक तथा तहसील व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। शिविर के दौरान नागरिकों की राजस्व व अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने पर विशेष जोर दिया गया। शिविर में नागरिकों को 7/12 उतारा, 8-अ उतारा तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा 7/12 अद्यतन करना, ई-मोजणी, पाणंद रास्तों से संबंधित कार्यवाही, अभिलेख सुधार हेल्पडेस्क, गैर-कृषि संबंधी मार्गदर्शन, पीएम किसान योजना, द्वितीय राशन कार्ड वितरण, लंबित फेरफार मामलों का निपटारा, तुकड़ेबंदी कानून के तहत कार्यवाही, सामाजिक सहायता योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य जांच, मुफ्त डिजिटल सातबारा, वनपट्टा जमीन पर नाम दर्ज करना, लक्ष्मी मुक्ति योजना तथा प्रॉपर्टी कार्ड जैसी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के समाधान शिविरों के माध्यम से महसूल विभाग से जुड़े लंबित कार्यों का तेजी से निपटारा हो रहा है। साथ ही शासन के ह्लसिंगल डे सर्विस डिलीवरीह्व उपक्रम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से मिल रही हैं। उपस्थित नागरिकों ने भी इस पहल को किसानों व आम लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक बताया।

छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर आयोजित

पालघर(उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र शासन के राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान झ चरण 1 के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय देहर्जे (तहसील विक्रमगड) में राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों के राजस्व एवं अन्य शासकीय सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। शिविर में नागरिकों को 7/12 उतारा, 8-अ उतारा सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा 7/12 अद्यतन करना, ई-मोजणी, पाणंद मार्ग से संबंधित कार्यवाही, अभिलेख दुरुस्ती हेल्पडेस्क, अकृषिक सुधारणा मार्गदर्शन, पीएम किसान योजना, दुय्यम राशन कार्ड वितरण, लंबित फेरफार प्रकरणों का निपटारा, तुकड़ेबंदी कानून के अंतर्गत कार्यवाही, सामाजिक आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य जांच तथा मुफ्त डिजिटल सातबारा जैसी कई सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं को ह्यबेबी किटह्व वितरित की गईं। साथ ही किसानों को एक-एक ट्रैक्टर और पावर टिलर का भी वितरण किया गया। शासन के सिंगल डे सर्विस डिलीवरी उपक्रम के तहत एक ही स्थान पर अनेक सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। वहीं इसी अभियान के तहत विरार में भी छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाया।कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी तेजस चव्हाण, तहसीलदार मयूर चव्हाण, ग्राम पंचायत सरपंच प्रसाद जाधव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

घाटकोपर पूर्व में सरकारी योजनाएं अब आपके दरवाजे पर शिविर लगाया

मुंबई (उत्तरशक्ति)। भाजपा विधायक पराग शाह के मार्गदर्शन में घाटकोपर पूर्व विधानसभा के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण लोकसेवा उपक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कुर्ला तहसीलदार कार्यालय की तरफ से आयोजित ह्लछत्रपति शिवाजी महाराज झ महाराजस्व समाधान शिविर अभियानह्व शनिवार, 2026 को शेठ धनजी देवशी राष्ट्रीय स्कूल में उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। ह्लसरकारी योजनाएं अब आपके दरवाजे परह्व संकल्पना के तहत लगाए गए इस कैंप में अलग-अलग सरकारी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, नई योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए एक खास कमरा भी बनाया गया था। दफकोड के जरिए डिजिटल जानकारी मिलने की वजह से लोगों को आसान और जल्दी सेवा मिली। घाटकोपर इलाके के सैकड़ों लोगों का जबरदस्त प्रतिसाद देखने को मिला। इस अवसर पर मुंबई की मेयर ऋतुताई तावड़े, नगरसेविका राखीताई जाधव, नगरसेवक धर्मेश गिरी, नगरसेविका निर्मिती कनाडे समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। यह पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'अंत्योदय' इस संकल्पना पर आधारित थी। उक्त उपक्रम प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने और एक ही छत के नीचे सरकार की अलग-अलग योजनाओं का फायदा देने की एक ईमानदार कोशिश थी। विधायक पराग शाह ने इस शिविर के सफल आयोजन के लिए कुर्ला तहसीलदार कार्यालय, ज़िला प्रशासन और बड़ी संख्या में मौजूद सभी नागरिकों का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस शिविर के बारे में नगरसेवक धर्मेश गिरी ने कहा कि विधायक पराग शाह के जरिए इलाके के नागरिकों को सरकार की अलग-अलग योजनाओं का फायदा देने के लिए यह शिविर लगाया गया था और नागरिकों की ओर से जबर्दस्त प्रतिसाद मिला।

हिंदू मुस्लिम एकता ही हमारे देश की खूबसूरती : इमरान प्रतापगढ़ी

फरहान आजमी द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष फरहान आजमी द्वारा आज हज हाउस में इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा सांसद वर्षा गायकवाड, प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अहमद खान, विधायक अमीन पटेल, विधायक पूर्व मंत्री असलम शेख, पूर्व विधायक अशोक भाऊ जाधव, मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, हरगुन सिंह सबरवाल, नगरसेवक सुफियान वनु, जिलाध्यक्ष अरशद आजमी, यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जीनत सबरीन, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निखिल रूपारेल, निजामुद्दीन राईन, अवनीश तीर्थराज सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस शानदार इफ्तार पार्टी के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष फरहान आजमी को बधाई देते हुए कहा कि आज इफ्तार पार्टी में जितने मुस्लिम समाज के लोग दिख रहे हैं, उनसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई बहने हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो परिचय आज इफ्तार पार्टी में देखने को मिल रहा है, यही गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा इस देश में भी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू मुस्लिम एक होकर इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे और देश को मजबूत बनाएं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। भिन्न-भिन्न धर्म और जातियों के बावजूद हम सभी एक होकर देश को अखंड और शक्तिशाली बनाते हैं। अंत में कार्यक्रम के आयोजक फरहान आजमी द्वारा समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

घाटकोपर के गांवदेवी में अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का आयोजन संपन्न

मुंबई (उत्तरशक्ति)। जय श्री स्वामी समर्थ मित्र मंडळ द्वारा होली स्नेह सम्मेलन के उपलक्ष्य में गांवदेवी, घाटकोपर (वेस्ट) स्थित भाजी मार्केट के सामने भाजपा कार्यालय परिसर में अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का भव्य आयोजन किया गया।

यह धार्मिक कार्यक्रम शनिवार, 14 मार्च को सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ है। आयोजकों के अनुसार रविवार, 15 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे पूर्णाहुति के साथ पूजा, हवन, आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन को सफल बनाने में मंडल के अध्यक्ष पंकज सिंह (ठाकूर), सचिव मुरलीधर यादव, कोषाध्यक्ष रंजीत पांडेय, उपाध्यक्ष सुनील उपाध्याय, राधे मोहन यादव, उपसचिव राजेश सिंह, चंदू शर्मा, उपकोषाध्यक्ष राजेश देवतवाल, रमेश साहु, प्रमुख सलाहकार संतोष सिंह, पारसनाथ सिंह, निगम सिंह, दलजीत पांडेय, कैलाश सिंह, राजकुमार यादव, मोहित चौबे, घनश्याम मिश्रा, ललित तिवारी, नीरज सिंह, दीपक सिंह, चंदू शिवहरे, सुरेन्द्र तिवारी, आलोक सिंह, जीतू मंडल, प्रवेश तिवारी, मिंझू सिंह, गिरीश गामा सिंह, संदीप यादव, मुकेश यादव, श्याम यादव, नीरज तिवारी, रोहित सिंह (सनी), लव निगम सिंह, अभिषेक सिंह (मोनू), दिलीप कैलाश सिंह, राहुल यादव, रितेश सिंह, रामसजीवन यादव, हर्ष यादव और प्रतीक यादव सहित मैदान व्यवस्था में पूर्वांचल मित्र मंडल, यूथ ब्रिगेड और तुलसी मानस मित्र मंडल के सभी कार्यकर्तगण और आस पास के श्रद्धालु भक्तगण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

नीला सन्स को जीत के बाद गुलदस्ता भेंट कर दी हार्दिक शुभकामनाएं

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी की मिरा-भायंदर क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 की उम्मीदवार श्रीमती नीला सन्स की जीत के बाद उन्हें गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन से मिली यह जीत क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी।श्रीमती नीला सन्स के उज्ज्वल कार्यकाल के लिए मंगलकामनाएं दी गईं और आशा व्यक्त की गई कि उनके नेतृत्व में वार्ड नंबर 18 में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।अगर चाहें तो मैं इसे थोड़ा और प्रोफेशनल न्यूज स्टाइल, हेडलाइन + सबहेडलाइन, या सोशल मीडिया पोस्ट फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ।

मनोर में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर आयोजित

नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का मिला त्वरित लाभ

पालघर (उत्तरशक्ति)। सरकार की पहल छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर अभियान (टप्पाझ1) के अंतर्गत पालघर जिले के मनोर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हाईस्कूल व महाविद्यालय परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता सांसद डॉ. हेमंत सवरा व विधायक विलास तरे ने की। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उपस्थित होकर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लिया।

इस शिविर में प्रशासन द्वारा सिंगल डे सर्विस डिलीवरी के माध्यम से कई सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान नागरिकों को 7/12 और 8-अ उतारे, डिजिटल सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड सहित विभिन्न प्रमाणपत्र वितरित किये गये। इसके साथ ही 7/12 अद्यतन, ई-मोजणी, पाणंद रास्तों से संबंधित कार्यवाही, अभिलेख दुरुस्ती हेल्पडेस्क, अकृषिक सुधारणा मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी, दुय्यम शिधापत्रिका वितरण, प्रलंबित फेरफार मामलों का निपटारा, तुकड़ेबंदी कानून के तहत कार्यवाही और सामाजिक आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच, वनपट्टों पर सातबारा नाम दर्ज करना, लक्ष्मी मुक्ति योजना जैसी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन भी दिया गया।

इस समाधान शिविर के माध्यम से राजस्व विभाग से जुड़े कई लंबित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। उपस्थित नागरिकों ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों से सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी व तेजी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों व किसानों को बड़ी राहत मिल रही है।इस अवसर पर भूसंपादन उपजिलाधिकारी महेश सागर, प्रांताधिकारी श्याम मदनुरकर, तहसीलदार रमेश शेंडगे, गटविकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के तहसीलस्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नालासोपारा में विकास कार्यों का शिलान्यास, बारिश में जलभराव से मिलेगी राहत

नालासोपारा (उत्तरशक्ति)। नालासोपारा वेस्ट के ओल्ड वार्ड नंबर 55 और न्यू वार्ड नंबर 11 के वार्ड कमिटी (ई) क्षेत्र में जीरो रोड एरिया से सेंट प्रोग्रेसिव स्कूल तक सड़क के किनारे नाले की प्रोटेक्टिव दीवार बनाने के महत्वपूर्ण विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। यह शिलान्यास कार्यक्रम नालासोपारा के विधायक राजन नाईक की उपस्थिति में उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

इस परियोजना के पूरा होने के बाद मॉनसून के दौरान इलाके में होने वाली जलभराव की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष मनोज पाटिल, कॉर्पोरेटर जितेंद्र पाटिल, कॉर्पोरेटर श्रीमती रसिका धागे, कॉर्पोरेटर श्रीमती नमिता पवार, बोर्ड प्रेसिडेंट सतीश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सभी गणमान्य अतिथियों, कार्यकताओं और क्षेत्र के नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया।

अगर आप चाहें तो मैं इसे छोटा सोशल मीडिया पोस्ट, हेडलाइन स्टाइल या अखबार के लिए और ज्यादा प्रोफेशनल न्यूज फॉर्मेट में भी बना सकता हूँ।

खोडाला में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर उत्साह के साथ संपन्न

नागरिकों को एक ही स्थान पर मिली कई शासकीय सेवाएं

पालघर(उत्तरशक्ति)। आम नागरिकों की राजस्व व अन्य शासकीय सेवाओं से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर (टप्पा-1) के अंतर्गत खोडाल मंडल स्तरीय शिविर ग्राम पंचायत कार्यालय खोडाला में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। शिविर को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला।

कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सभापति प्रदीप वाघ, अपर निवासी उपजिलाधिकारी रविंद्र राजपूत तथा मिलिंद झोले के हाथों किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। शिविर में नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए कई शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। इसमें जाति प्रमाणपत्र व डोमिसाइल प्रमाणपत्र वितरण, आधार कार्ड पंजीकरण व सुधार, 7/12 उतारा अद्यतन व डिजिटल 7/12 वितरण, राशन कार्ड से संबंधित लाभ, अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क, अकृषिक सुधार मार्गदर्शन तथा लंबित फेरफार मामलों का निपटारा शामिल था। इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक अर्थसहाय्य योजनाओं का लाभ, लोकसेवा हक्क कानून के अंतर्गत त्वरित सेवाएं, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी व लाभ, आयुष्मान भारत कार्ड पंजीकरण व वितरण, प्राकृतिक आपदा अनुदान के लिए ई-केवाईसी तथा मतदाता पंजीकरण व विलोपन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किये गये। वहीं उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय की ओर से सनद व ई-मोजणी प्रमाणपत्र दिए गए। पंचायत समिति समाजकल्याण विभाग और पशुसंवर्धन विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस अवसर पर लाभ प्रदान किये गये।जिला उद्योग केंद्र की ओर से युवाओं व नागरिकों को उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

साथ ही आदिवासी विकास विभाग की योजनाओं, कलम 85 आवेदन, तुकडेबंदी कानून तथा लक्ष्मीमुक्ति योजना के बारे में मार्गदर्शन भी किया गया। इस शिविर के माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे अनेक शासकीय सेवाएं मिलने से बड़ी राहत मिली।

पालघर में छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर में पहुंचे डॉ हेमंत सवरा

पालघर। पालघर के खासदार डॉ. हेमंत सावरा ने पालघर में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से संवाद किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े विभिन्न मामलों के समाधान के लिए चल रही इस पहल का निरीक्षण किया।

इस शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों, किसानों, छात्रों और महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निवारण करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुँचाना है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएँ प्रस्तुत कीं, जिन पर अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई।

डॉ. सावरा ने कहा कि सरकार नागरिकों की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। इस तरह के समाधान शिविर प्रशासन को अधिक जनकेंद्रित और तेजी से काम करने वाला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। यह पहल स्थानीय स्तर पर प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं को लोगों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।

उत्तर भारतीय संघ की फूलों की होली में दिखा सामाजिक एकता का संगम

मुंबई (उत्तरशक्ति)। बांद्रा पूर्व स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में शनिवार को उत्तर भारतीय संघ की ओर से भव्य होली स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और फूलों की होली खेलते हुए एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। गीत-संगीत और पारंपरिक मिलन के माहौल से पूरा परिसर रंग और उत्साह से सराबोर हो गया। इस अवसर पर अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह ने सभी को होली की शुभकामनांए दी और आम उत्तरभारतीय के प्रति संघ की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ संघ हमेशा डटा रहेगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह ने भाजपा विधायक राजहंस सिंह का विशेष रूप से सम्मान किया गया । इस मौके पर राजहंस सिंह ने कहा कि वे उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के विकास और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान समाजसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों ने सहयोग भी दिया। विशाल सिंह ने पांच लाख रुपए का चेक देकर संघ के विशेष ट्रस्टी बनने की घोषणा की। विशाल सिंह के पिता अशोक सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीय संघ को मजबूत बनाने में बाबू आरएन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके प्रयासों से ही संस्था लगातार आगे बढ़ी। समारोह में सांस्कृतिक रंग भी खूब देखने को मिला। गायक राकेश तिवारी और उनकी टीम ने पारंपरिक और लोकप्रिय होली गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को और अधिक रंगीन बना दिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रीति भोज (बाटी-चोखा) का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, रामबक्श सिंह, कृष्णामणि शुक्ला, विजय सिंह (मालाड), शिवनारायण सिंह, जसवंत यादव, सुरेश दुबे, रमेश बहादुर सिंह, संजय सिंह, डॉ. किशोर सिंह, देवेंद्र तिवारी, अशोक दुबे, अवनीश सिंह, बीड़ी सिंह, ओमप्रकाश सिंह, श्रीनिवास तिवारी, अजय कुमार सिंह, अंतेश सिंह, नंदलाल उपाध्याय, राजेश सिंह, संजू सिंह, सीताराम यादव, प्रह्लाद पांडेय, रामनयन शर्मा, रेणू मल्लाह, विजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी, आदित्य दुबे, विशाल सिंह, आदित्य सिंह सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के महामंत्री देवेंद्र तिवारी ने किया।

नगरसेविका अपर्णा पाटिल और निम्मी दोशी ने वसई विकासिनी कॉलेज के कार्यक्रम में लिया हिस्सा

वसई रोड (उत्तरशक्ति)। वसई ईस्ट स्थित वसई विकासिनी कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट्स में आयोजित सालाना आर्ट एग्ज़िबिशन और बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में नगरसेविका श्रीमती अपर्णा पाटिल को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 23 की नगरसेविका श्रीमती निम्मी दोशी भी उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कला कार्यों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, मेहनत और रचनात्मकता को देखकर श्रीमती अपर्णा पाटिल ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं और कला के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।

इस अवसर पर हरीश बेदी (कामगार अघाड़ी प्रेसिडेंट, वसई रोड डिवीजन) और पूर्व नगरसेवक छोटू आनंद भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया और कला व संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों को लगातार जारी रखने की बात कही गई।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

रंगदारी न मिलने पर खुद रची थी विस्फोट की साजिश, खुश्बू किन्नर गिरफ्तार

चंदौली (उत्तरशक्ति)। बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में पिछले वर्ष हुए बम विस्फोट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए शुक्रवार को खुश्बू किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि रंगदारी न मिलने पर खुश्बू किन्नर ने खुद ही विस्फोट की साजिश रची थी और कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी।

जानकारी के अनुसार मोहरगंज पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित खुश्बू किन्नर के तीन मंजिला मकान में 21 दिसंबर 2025 की रात बम विस्फोट हुआ था। घटना के समय मकान में सो रहे 12 से अधिक लोग दहशत में आ गए थे। मामले में पुलिस ने बलुआ सराय के दो युवकों सहित 12 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया था और दो आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। जनवरी माह में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास सिंह को रिमांड पर लेकर सराय गांव से एक पिस्टल तथा विस्फोट में इस्तेमाल की गई जिलेटिन रॉड बरामद की थी। वहीं आरोपियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी द्वारा मामले की जांच कराई गई।

> **इस संबंध में एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि खुश्बू किन्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।**

एडीजी के निर्देश पर एएसपी जौनपुर द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि खुश्बू किन्नर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिन लोगों को आरोपी बनाया था, उनसे लगातार रंगदारी की मांग कर रही थी। रंगदारी न मिलने पर उसने खुद ही अपने घर में विस्फोट की साजिश रची और लोगों को फंसाने की कोशिश की।

जांच के आधार पर खुश्बू किन्नर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने खुश्बू किन्नर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए चालान कर दिया।

जौनपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, संभल के सीओ के बयान की निंदा

2027 चुनाव को लेकर दिया बड़ा संकेत

डॉ.इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शनिवार को जौनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान बंटी द्वारा शहर में आयोजित भव्य इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इफ्तार कार्यक्रम में हजारों की संख्या में रोजेदारों और मेहमानों ने भाग लिया, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हुए आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया।

इफ्तार पार्टी के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में शौकत अली ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संभल के सीओ कुलदीप कुमार द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की बैठकों में किसी समुदाय विशेष का अपमान किया जाता है तो मुस्लिम समाज को ऐसी बैठकों का बहिष्कार करना चाहिए। संवाद हमेशा सम्मान के साथ होना चाहिए, किसी समुदाय को अपमानित करना उचित नहीं है।

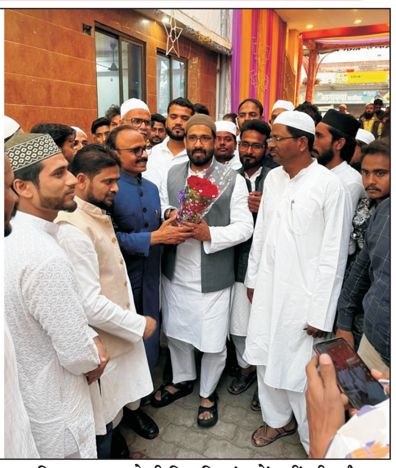

इजराइल के समर्थन में कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय ऐसी टिप्पणियां क्यों नहीं की गईं।

आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं।

गैस सिलेंडर को लेकर लगने वाली लाइनों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लाइन तो भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देती है। जब-जब लोग लाइन में लगे हैं, तब-तब बीजेपी को फायदा हुआ है, चाहे वह नोटबंदी का समय रहा हो या कोविड काल। वहीं पीडीए के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह अब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। अक्टक को बी-टीम कहे जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और समय आने पर इसका जवाब देगी। इस अवसर पर पूर्वांचल संयुक्त सचिव जावेद सिद्दीकी, प्रदेश संयुक्त सचिव एवं प्रभारी सैय्यद मुंतज़िर, जिला महासचिव शाह नेयाज अहमद, इरशाद अहमद, यासिर खान, निखिलेश सिंह, सलीम खा, डॉ .गुलाम रब्बानी खान, मजनू राम गौतम, कामरान अहमद, अकरम, अम्लेश राजभर सहित सभी विधानसभा अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष इमरान बंटी ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

गाँव में अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं ने किया प्रदर्शन

थाना प्रभारी को दिया प्रार्थना-पत्र देकर किया कार्यवाई की मांग

खेतासराय,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अवैध रूप से ग्राम में शराब की बिक्री को लेकर शनिवार को गाँव की महिलायें आक्रोशित होकर थाने में प्रदर्शन की इसके पश्चात दो दर्जन महिलायें एकजुट होकर थाना प्रभारी को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

महिलाओं का आरोप है कि तारगहना गाँव के एक युवक द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है इनका कहना है कि शराब की इस अवैध बिक्री के कारण युवाओं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। शराब पीकर झगड़े-फसाद और हुड़दंग की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिससे गाँव की महिलाओं और बच्चों को बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस होती है। उक्त गाँव निवासी सोना, ज्ञानमती, प्रमिला, पूनम, कुसुम, जड़ावती, चनवा, नीलम, सिलोचना, राधा, सरोज, दसिया समेत महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रह सके।

खेल और शिक्षा में बेटियां रच रहीं इतिहास: ओमप्रकाश यादव

ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन में 100 छात्राओं को मिली खेल सामग्री किट

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खुटहन क्षेत्र के ग्राम विकास इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने वाली 100 छात्राओं को खेल सामग्री किट वितरित की गई। भारतीय रेल वित्त निगम के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को ट्रैक सूट, जूते, मोजे सहित अन्य खेल सामग्री प्रदान की गई, जिससे छात्राओं के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय रेल भूमि विकास प्राधिकरण के प्रबंधक ओमप्रकाश यादव (आईआरएस) ने छात्राओं को खेल सामग्री वितरित करते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल दोनों ही व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेल से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और

मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. रमेश चंद्र यादव ने कहा कि छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं। इससे बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खेल के साथ-साथ शिक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय का प्रयास है कि छात्राओं को हर क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी बराबर महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को खेल सामग्री मिलने से उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा और वे आगे चलकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। संचालन ईश्वरदेव यादव ने किया। इस अवसर पर श्रीराम कुमार यादव, राम शिरोमणि वर्मा, डॉ. सुनील कांत तिवारी, अनिल यादव सहित विद्यालय के शिक्षक-कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

पत्रकार रत्न से हुए सम्मानित

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं संस्कार भारती प्रयागराज के कलात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरन्तर अपने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रसारित करने तथा भारतीय कला संस्कृति उत्थान के लिए वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा प्रसाद मिश्र उजाला शिखर हिंदी दैनिक, युवा पत्रकार अजय मिश्रा दैनिक तीर्थराज टाइम्स, मुनिश्वर जायसवाल दैनिक प्रथम मंच गाजियाबाद, एवं पारुल सिंह ब्यूरो हरदोई दैनिक उजाला शिखर को पत्रकार-रत्न सम्मान से प्रयागराज में आज सम्मानित किया गया। राज्य ललित कला अकादमी संस्कृति विभाग के माननीय सदस्य एवं संस्कार भारती प्रयागराज के कला संयोजक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि-चित्रकार रवीन्द्र कुशवाहा ने अपने चित्रकला स्टूडियो करेला बाग कॉलोनी प्रयागराज के मीडिया बैठक एवं कला परिचर्चा के दौरान अंगवस्त्र-शाल, प्रशस्ति-पत्र, स्मृति चिन्ह पेंटिंग एवं कलाग्रंथ प्रदान कर उपरोक्त सम्मानित पत्रकारों को पत्रकार-रत्न सम्मान से सम्मानित किया और कहा कि दैनिक समाचार पत्र एवं मीडिया के कारण ही भारतीय कला संस्कृति का वास्तविक प्रसार प्रचार हो पाता है जिसके कारण ही भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, जिसमें भारत के चौथे स्तंभ सम्मानित पत्रकार व मीडिया कर्मियों का अमूल्य योगदान एवं समर्पण दिखाई पड़ता है।

सिलेंडर के लिए अधिक वसूली का आरोप, उपभोक्ताओं ने एसडीएम से की शिकायत

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। क्षेत्र में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि गैस एजेंसी संचालक निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूल रहे हैं और समय पर सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित उपभोक्ताओं ने एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बम्मावन गांव निवासी अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 4 मार्च को गैस सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन दस दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। उनका आरोप है कि एजेंसी संचालक स्टॉक न होने का बहाना बनाकर अधिक कीमत पर चोरी-छिपे अन्य लोगों को सिलेंडर बेच रहा है। इसी तरह गोबरा गांव के ब्रह्मानंद मिश्रा ने 2 मार्च को सिलेंडर बुक कराया था। उनके मोबाइल पर डिलीवरी का संदेश भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला।

वहीं केराकत नगर निवासी नितिन सोनकर ने बताया कि वे पिछले तीन दिनों से मोबाइल के माध्यम से गैस बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो पा रही है। जब वे एजेंसी कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों ने नेटवर्क समस्या का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया।

पीड़ित उपभोक्ताओं ने इस मामले में एसडीएम शैलेन्द्र कुमार से शिकायत कर एजेंसी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर एसडीएम शैलेन्द्र कुमार ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि चार से पांच दिनों के भीतर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अनाधिकृत गैस सिलेंडर भंडारण पर छापा, तीन लोग गिरफ्तार

खुटहन,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शासन के निर्देश पर खुटहन थाना पुलिस और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम ने शनिवार को अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद किए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, दिनांक 14 मार्च 2026 को खुटहन से जौनपुर लिंक मार्ग पर स्थित ग्राम धमौर में छापेमारी की गई। इस दौरान अलग-अलग स्थानों से कुल 81 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान दिनेश प्रजापति पुत्र रामप्रसाद प्रजापति निवासी धमौर खास, थाना खुटहन के घर से 38 खाली इंडेन मार्का घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा), 1 भरा हुआ इंडेन सिलेंडर तथा 10 खाली भारत गैस सिलेंडर, कुल 49 सिलेंडर बरामद हुए।

वहीं बृजेश कुमार प्रजापति पुत्र स्व. लालबहादुर प्रजापति निवासी ग्राम बंदनपुर, थाना खुटहन के दुकान/जनसेवा केंद्र से 14 खाली इंडेन गैस सिलेंडर और 1 भरा हुआ भारत गैस सिलेंडर, कुल 15 सिलेंडर बरामद किए गए।

इसके अलावा अशोक विश्वकर्मा पुत्र रामलखन विश्वकर्मा निवासी धमौर, थाना खुटहन के दुकान/जनसेवा केंद्र से 12 खाली इंडेन तथा 5 खाली भारत गैस सिलेंडर, कुल 17 सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि इन सिलेंडरों को अनाधिकृत रूप से भंडारित कर बेचा जा रहा था, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कंट्रोल ऑर्डर 2000 (यथासंशोधित) का उल्लंघन है।

इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मियांपुर की शाही मस्जिद में तरावीह मुकम्मल, हाफिज मोहम्मद शाफे का सम्मान

मो.फैसल सिद्दीकी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। रमजान के पाक महीने में मियांपुर स्थित शाही मस्जिद में अलविदा जुम्मे के दिन तरावीह मुकम्मल की गई। इस दौरान हाफिज मोहम्मद शाफे ने तरावीह की नमाज पढ़ाई और पूरे रमजान माह में अकीदतमंदों को कुरान पाक सुनाया। तरावीह मुकम्मल होने के बाद मस्जिद में मुल्क की तरक्की, अमन-ओ-अमान और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर हाफिज मोहम्मद शाफे को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सोनू, सैकी, ख्वाजा अहमद हसन, मोहम्मद सरताज, वसीक अहमद, नाजिश सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने तबर्रुक हासिल किया और एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते हुए अपने-अपने घरों को रवाना हुए।

पट्टीदारों ने माँ बेटी को मारपीट कर घायल किया

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। मेंहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पट्टी पुरवा में रविवार सुबह करीब 7 बजे जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों ने एक महिला और उसकी दो बेटियों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को पहले सीएचसी मेंहनगर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय अनिता पत्नी रामविलास सरोज अपने चिन्हित भूमि पर वर्षों से टीनशेड रखकर गुजर-बसर कर रही थीं। रविवार की सुबह आरोप है कि उनके पट्टीदार संजय, दिलीप और हरिचंद्र सहित कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे और टीनशेड पर लाठी-डंडों से प्रहार करने लगे तथा सामान फेंकने लगे। अनिता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मां को पिटता देख उनकी पुत्रियां नंदिनी (24 वर्ष) और संजना (16 वर्ष) भी मौके पर पहुंचीं तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद एक पड़ोसी की मदद से तीनों घायलों को ऑटो रिक्शा से मेंहनगर थाने ले जाया गया। वहां से 108 एंबुलेंस की सहायता से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहनगर भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस संबंध में घायल अनिता ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दे दी है।

वसुधैव कुटुंबकम ही सनातन धर्म का मूलमंत्र: डॉ.अवनीश

मछलीशहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अवनीश सिंह ने मीडिया से की बातचीत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वसुधैव कुटुंबकम ही सनातन धर्म का मूलमंत्र है। मानवता की सेवा ही मनुष्य की असली पहचान होती है और समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है। सनातन धर्म सभी को जोड़ने और विश्व कल्याण का संदेश देता है। इसलिए किसी भी माध्यम से किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार जनकल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। उक्त बातें मछलीशहर में शुक्रवार की शाम युवराज फैमिली रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ. अवनीश सिंह गुरुजी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कहीं। उन्होंने कहा कि शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल और रेस्टोरेंट खुलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। साथ ही क्षेत्र के व्यापार को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की असली पहचान परिश्रम, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सेवा भाव से बनती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह के आधुनिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है।

उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों को बेहतर सेवा और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मछलीशहर के जिलाध्यक्ष डॉ. अजय सिंह के नेतृत्व में मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ज्ञान प्रकाश सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरव, अभिषेक सिंह परमार (जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा), आजाद सिंह (अध्यक्ष ठेकेदार संघ जौनपुर), भानु प्रकाश सिंह, मनीष सिंह, सोनू सिंह, चेतन सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, स्वदेश सिंह, पीयूष सिंह, शुभम सिंह, राधेश्याम विश्वकर्मा (पूर्व मंडल अध्यक्ष), रणविजय सिंह (पूर्व मंडल अध्यक्ष) तथा स्कंद पटेल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

केराकत में राशन कार्ड की गड़बड़ियों से कालाबाजारी का आरोप, उपभोक्ताओं की शिकायतों का अंबार

केराकत,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि राशन कार्ड में जानबूझकर खामियां बनाकर कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है और कार्ड धारकों से अवैध वसूली भी की जा रही है। कस्बे के सिपाह मोहल्ले की निवासी नजमा ने शिकायत की है कि उनके राशन कार्ड पर एक अज्ञात हिन्दू महिला का नाम मुखिया के रूप में दर्ज कर दिया गया है। नजमा का कहना है कि उन्होंने कई बार कोटेदार से उस महिला का नाम हटाने के लिए कहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह कस्बे के मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनकी मां फातिमा के राशन कार्ड पर उनका तथा उनके भाई मोहम्मद कासिम का नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए वह पिछले दो महीनों से पूर्ति कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

वहीं सिपाह मोहल्ले की ही रुखसाना ने आरोप लगाया कि उनका मकान सिपाह मोहल्ले में होने के बावजूद राशन कार्ड पर पता नालापार दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सही पता दर्ज कराने के लिए वह कई महीनों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि राशन वितरण के दौरान कोटेदार अंगूठा तो लगवा लेता है लेकिन पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं देता बल्कि अपने पास रख लेता है। ढेर सारी पर्चियां इकट्ठा हो जाने पर वह उसे बड़ी सफगोई से जला देता है और राख नाले में बहा देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनमानी और इस तरह की गड़बड़ियों के कारण कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही! संविदा कर्मियों की जान जोखिम में, जिम्मेदार कौन?

सुशील कुमार तिवारी

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रॉबर्ट्सगंज और पिपरी दो विद्युत उपखंडों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर अनदेखी सामने आ रही है। आए दिन बिजली लाइनों पर काम करते समय संविदा श्रमिक घायल हो रहे हैं या फिर अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विभागीय जिम्मेदारों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली लाइनों की मरम्मत, ट्रांसफार्मर रखरखाव, मीटर लगाने, बकाया बिल वसूली, लाइन काटने, 11 हजार और एलटी लाइनों के आसपास पेड़ों की डालियां काटने जैसे जोखिम भरे कार्य अधिकतर संविदा कर्मियों से ही कराए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते।

संविदा कर्मियों का आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर केवल हेलमेट और रेडियम जैकेट दे दी जाती है, जबकि सेफ्टी बेल्ट, सुरक्षा जूते, ग्लव्स, अर्थ रॉड, अर्थ चेन और सीढ़ी जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। यदि कोई कर्मी इन उपकरणों की मांग करता है तो उसे अपने पैसे से खरीदने की सलाह दे दी जाती है। गौरतलब है कि संविदा कर्मियों को मात्र लगभग 8 हजार रुपये के अल्प वेतन पर काम करना पड़ता है। ऐसे में

उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण खरीदने की मजबूरी खड़ी हो जाती है। जबकि नियम के अनुसार इन उपकरणों की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है, जिसे लाइन मेंटेनेंस और बिल वसूली का टेंडर दिया जाता है।

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, विद्युत वितरण प्रणाली पर लोड भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। मैनपावर की कमी के कारण संविदा कर्मियों से अधिक काम लिया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब विभाग के पास संसाधन और बजट उपलब्ध है तो मैनपावर बढ़ाने में आखिर दिक्कत क्या है।

वहीं, संविदा कर्मियों का यह भी कहना है कि यूपीपीसीएल अध्यक्ष के आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मी फेसियल अटेंडेंस में पांच मिनट भी देर करता है तो उसे लापरवाह मानते हुए, नौकरी से हटाने की चेतावनी दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर उनसे रोजाना 8 घंटे की निर्धारित ड्यूटी के बजाय लगभग 12 घंटे तक काम कराया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि संविदा कर्मियों की सुरक्षा और अधिकारों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है–विद्युत विभाग के अधिकारी और कंपनी या फिर वे संविदा श्रमिक, जो अल्प वेतन में अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं।

क्यों याद कर रही उसको

नशे में डूबा इंसान
कभी समझ नहीं पाएगा तुझको,
फिर क्यों यूँ हर पल
परेशान कर रही है तू उसको।
क्यों फरियाद करती है उससे,
जो सुन ही नहीं रहा तुझको,
रुलाया है जिसने हर मोड़ पर
क्यों याद कर रही है तू उसको।
कितना समझाया था दिल ने तुझको,
पर दिल दे बैठी थी तू उसको,
जो तेरी खामोशी भी न समझा
क्यों अपना बना लिया उसको।
रातों को जगाया था तुझको,
बातों से बहलाया था तुझको,
झूठे वादों के जाल में
सपनों में उलझाया था तुझको।
यूँ तन्हा छोड़ गया वो तुझको,
आँसुओं में डुबो गया तुझको,
फिर भी दिल के किसी कोने में
क्यों बसा रखा है तूने उसको।
यादों में क्यों बसाया है उसको,
जो याद भी नहीं करता तुझको,
क्यों हर दर्द सहती है तू
क्यों इतना चाहती है उसको।
जिसने तेरी कद्र न जानी,
क्यों मान बैठी तू अपना उसको,
जो हर बार तोड़ गया तुझको
क्यों जोड़ने चली है तू उसको।
सोच जरा, क्या पाया तूने
अपना सब कुछ देकर उसको,
खुद को ही खो बैठी तू
बस यादों में ढूँढती रही उसको।
अब वक्त है खुद को संभालने का,
आँसुओं से रिश्ता तोड़ने का,
जो तेरी कीमत समझ न सका
अब भूल भी जा तू उसको।
तू खुद में ही एक दुनिया है,
क्यों छोटा समझती है खुद को,
जिसे तेरी मोहब्बत की कद्र न हो
क्यों सौंप बैठी है दिल उसको।
उठ, अब खुद को पहचान जरा,
अपने सपनों को थाम जरा,
जो चला गया उसे जाने दे
अब खुद से प्यार कर जरा।

नसु एंजल रामटेके
नागपुर, महाराष्ट्र

चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का शटर चाढ़कर की चोरी,जांच में जुटी पुलिस

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर के गोलावार्ड निवासी मुन्ना सेठ की रामपुर भौरा मोड़ के पास आरुष ज्वेलर्स नाम से दुकान है। दुकान स्वामी के अनुसार शनिवार की रात अज्ञात चोर दुकान का शटर चाढ़कर अंदर घुस गए और काउंटर में रखे 8500 रुपये नगदी, करीब पांच ग्राम सोने के आभूषण तथा लगभग 50 ग्राम चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि चोरों ने दुकान में रखी आलमारी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो सके। यदि आलमारी टूट जाती तो उसमें रखा अन्य कीमती सामान भी चोरी हो सकता था। जाते समय चोर दुकान में लगा डीवीआर भी उठा ले गए, जिससे घटना की फुटेज न मिल सके। वहीं बगल की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि उस दुकान के डीवीआर में एक संदिग्ध की गतिविधि कैद हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर जब मुन्ना सेठ दुकान पर पहुंचे तो चोरी की घटना देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके व वरदात का निरीक्षण कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।वही चोरी की घटना से ग्रामीणों में भय का व्याप्त है माहौल।

दालमंडी में तीन मकानों पर चला बुलडोजर, फोर्स रही तैनात

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता है, वहां जेसीबी और मजदूरों की सहायता से पुराने और जर्जर हिस्सों को हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पहले ही संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस देकर मकान खाली करने की सूचना दी गई थी। कार्रवाई के दौरान करीब 200 मजदूरों को लगाया गया है, जो भवनों के पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मलबा हटाने के बाद सड़क के दोनों ओर की वास्तविक चौड़ाई का आकलन किया जाएगा, ताकि आगे की कार्ययोजना उसी के अनुसार तैयार की जा सके। कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार घोषणा कर लोगों को जानकारी दी जा रही थी। लाउडस्पीकर के माध्यम से आसपास के निवासियों और दुकानदारों को मकान खाली करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लगभग 25 भवनों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

सरकारी नाले की जमीन पर पिलर गाड़कर कब्जे का आरोप, राजस्व टीम ने की पैमाइश

-विशाल सोनी

जौनपुर रोड स्थित नाले के किनारे निर्माण की शिकायत पर कानूनगो-लेखपाल ने किया मौका मुआयना, दोनों तरफ की चौड़ाई नापी

शाहगंज, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर के जौनपुर रोड स्थित नजीराबाद इलाके में गंदे नाले की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने रविवार को मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। टीम ने नाले के दोनों किनारों की चौड़ाई की पैमाइश करते हुए स्थिति का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार नजीराबाद स्थित नहरनुमा गंदे नाले के किनारे एक व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण के लिए नाले से सटाकर पिलर खड़ा किए जाने की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर कस्बा कानूनगो संजय सिंह और लेखपाल अशोक कुमार की टीम मौके पर पहुंची और नाले के आसपास की जमीन की मापी कर स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने नाले के दोनों तरफ की चौड़ाई नापकर राजस्व अभिलेखों से मिलान करने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जब तहसीलदार आशीष सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वह इस समय दरोगा भर्ती परीक्षा की ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें मामले की फिलहाल जानकारी नहीं है।

स्वयंसेवक जब समाज में उतरते हैं तो उनको सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होता है

राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर सकुशल संपन्न

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के राजातालाब आराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय जखिनी के प्राचार्य संतोष सिंह की अध्यक्षता एवं कार्यक्रम अधिकारी आनंद सिंह के नेतृत्व में नरसड़ा ग्राम सभा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित विशेष सात दिवसीय शिविर सकुशल संपन्न हुआ। शिविर के दौरान स्वयंसेवको ने नरसड़ा गांव में स्वच्छता एवं पर्यावरण जन जागरूकता रैली निकाली। गांव में घर-घर जाकर महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तथा स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हुए गांव के गालियों तथा सड़कों सहित आसपास साफ सफाई कर श्रमदान किया। शिविर के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि तहसीलदार राजातालाब शालिनी सिंह ने शिविर के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जब स्वयं सेवक समाज से जुड़ता है तब वह सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करता है। प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह ने कुशलता पूर्वक शिविर को संपन्न कराने वाले प्रतिभागी सभी स्वयंसेवको की सराहना किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ आनंद सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन स्वयंसेविका रितु मिश्रा तथा धन्यवाद ज्ञापन नंदिनी मौर्य ने की। इस अवसर पर वेद प्रकाश दुबे ,योगेश चंद पटेल, प्रोफेसर कैलाश उजाला डॉक्टर अवनीश चंद्र, डॉक्टर कैलाश राम पुरुषोत्तम सिन्हा,राजेंद्र यादव राजन इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन डीएम ने किया औचक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की परीक्षा के दूसरे दिन जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डॉ. राममनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज और मुक्तेश्वर बालिका इंटर कॉलेज समेत कई केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाए, सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाए और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जिन्होंने दलितों, शोषितों और पिछड़ों को राजनीतिक चेतना जगाया: डॉ रागिनी सोनकर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निदेर्शानुसार समाजवादी पार्टी जौनपुर के द्वारा नगर के होटल रिवर व्यू में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की 92 वीं जयंती भव्य समारोह आयोजित कर मनाई गई।

सर्वप्रथम उपस्थित पार्टीजनों ने मान्यवर कांशीराम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया तथा उनके विचारों पर चलने का पुनः संकल्प लिया। जनपद के कोने कोने से पीडीए समाज और बहुजन समाज के लोग मान्यवर कांशीराम साहब की फोटो हाथ में लेकर पैदल गाड़ियों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल होटल रिवर व्यू पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने तथा संचालन ज़िला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

उक्त अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मछलीशहर की लोकप्रिय विधायक डॉ रागिनी सोनकर ने कहा कि बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब दलितों, शोषितों और पिछड़ों को राजनीतिक चेतना जगाकर 'हुक्मरान' बनने का सपना दिखाया और आज हम जैसे लोग सांसद और विधायक बनकर शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज उठा रहे लेकिन हम पीडीए (बहुजन समाज) को तभी अधिकार दिला पाएंगे जब सत्ता में हम हुक्मरान होंगे जिसके लिए पीडीए समाज, बहुजन समाज को अखिलेश यादव के साथ एकजुट हो कर आना पड़ेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर हम सभी को उनके उद्देश्यों बहुजन समाज (दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक) को शिक्षित, संगठित और जागरूक करना है और एकजुट होकर सत्ता प्राप्त करना है पीडीए सरकार बनाना है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई, विधायक लकी यादव, विधायक पंकज पटेल, पूर्व मंत्री श्रीराम यादव, पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, पूर्व विधायक राजनरायन बिंद, पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान, पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संगीता यादव, पूर्व प्रत्याशी संजय सरोज, दीपचंद राम, विवेक रंजन यादव, सुशील दुबे, महेंद्र यादव, सुरेश यादव हवलदार चौधरी, साहबलाल गौतम, अमित गौतम, हरिश्चंद प्रभाकर, हीरालाल विश्वकर्मा, श्यामबहादुर पाल,राजेंद्र यादव टाइगर, उमाशंकर पाल, डॉ.सरफराज , महेंद्र यादव नैपाल, डॉ. जंगबहादुर यादव, गामा सोनकर, कमलेश यादव लाल मोहम्मद राईनी, आनंद गुप्ता, श्यामनारायण बिंद, रामजतन यादव, वीरेंद्र यादव, निजामुद्दीन अंसारी, राम अकबाल यादव, सूर्यभान यादव, नंदलाल यादव, रामू मौर्य सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से शकील अहमद, भूपेश पाण्डेय, मालती निषाद, राहुल त्रिपाठी, गुलाब यादव रीठी, दीपक विश्वकर्मा, ऋषि यादव,विकास यादव, विनय जी, रविन्द्र मौर्य, गुड्डू सोनकर, दिलीप प्रजापति, आनंद गुप्ता, अशोक यादव नायक, अमजद अंसारी, ताज मोहम्मद सहित हजारों की संख्या में हाथों में मान्यवर कांशीराम साहब की फोटो लिए पीडीए समाज के लोग और सपाजन उपस्थित रहे।

दालमंडी में तीन मकानों पर चला बुलडोजर, फोर्स रही तैनात

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता है, वहां जेसीबी और मजदूरों की सहायता से पुराने और जर्जर हिस्सों को हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पहले ही संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस देकर मकान खाली करने की सूचना दी गई थी।

कार्रवाई के दौरान करीब 200 मजदूरों को लगाया गया है, जो भवनों के पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मलबा हटाने के बाद सड़क के दोनों ओर की वास्तविक चौड़ाई का आकलन किया जाएगा, ताकि आगे की कार्ययोजना उसी के अनुसार तैयार की जा सके। कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार घोषणा कर लोगों को जानकारी दी जा रही थी। लाउडस्पीकर के माध्यम से आसपास के निवासियों और दुकानदारों को मकान खाली करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लगभग 25 भवनों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

व्यापार मंडल ने व्यापारियों में मिष्ठान बांटते हुए खुशी व्यक्त किया,सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस अब आजीवन वैध की घोषणा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। व्यापार मंडल ने गल्ला मंडी स्थित सभी व्यापारियों में मिष्ठान वितरण करते हुए सरकार के द्वारा इस निर्णय की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने कहा कि खाद्य लाइसेंस को आजीवन मान्यता देने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है।खाद्य व्यापार से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को बधाइयां, नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की लंबे समय से चली आ रही मांग थी सरकार का यह निर्णय व्यापारियों के लिए राहत भरा निर्णय है।

इससे व्यापार में सुगमता बढ़ेगी।प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी एवं प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से छोटे-बड़े व्यापारियों को बार-बार नवीनीकरण की झंझट और अनावश्यक कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्रम में जिला महामंत्री रामकुमार साहू, नगर महामंत्री मुन्नालाल अग्रहरि, नगर कोषाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, अनाज व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष सुनील जायसवाल,मीडिया प्रभारी यशवंत साहू, विजय अग्रहरी, चेतन टंडन, दिनेश अग्रहरि, मंगला साहू, विजय जायसवाल, संजय साहू, अरुण कपूर,मनोज साहू, गुलजारी लाल गुप्ता, दिलीप साहू आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ट्रैक्टर के धक्के से टूटा विद्युत पोल, बड़ा हादसा टला

कोन, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रोरवा के पूर्वी टोला में शनिवार दोपहर एक ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल और तार टूटकर गिर गए। गनीमत रही कि उस समय पोल के नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों के अनुसार ट्रैक्टर मिट्टी गिराने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान चालक से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और उसने विद्युत पोल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल और उससे जुड़े तार टूटकर नीचे गिर गए। घटना के बाद क्षेत्र के लगभग 20 से 25 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना विद्युत विभाग के कर्मी अनिल कुमार को दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर तार को ट्रांसफार्मर से अलग कर दिया। साथ ही घटना की जानकारी अवर अभियंता को भी दी गई। बताया जा रहा है कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय बिजली आपूर्ति चालू थी। संयोग अच्छा रहा कि एलटी लाइन के नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। ग्रामीणों के अनुसार ट्रैक्टर रोरवा के प्रधानपति का बताया जा रहा है। इस संबंध में अवर अभियंता गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना एसडीओ पिपरी को दे दी गई है और मामले में संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने भेजी शिक्षक की पाती

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के विरोध में घोषित चरणबद्ध आंदोलन के तहत रविवार को जौनपुर इकाई के सभी 23 घटक संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति, माननीय मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित शिक्षक की पाती पोस्टकार्ड के माध्यम से कलेक्ट्रेट स्थित डाकघर से भेजी गई। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता थोपना न्यायसंगत नहीं है। महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में अटेवा मंडलिक मंत्री संदीप चौधरी, अटेवा जिला मंत्री इंदु प्रकाश यादव, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिला मंत्री सत्य प्रकाश मिश्र, पीएसपीएसए प्रदेश संगठन मंत्री विकास सिंह, यूटा प्रांतीय महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष डॉ. हेमंत सिंह, यूटा जिला महामंत्री राजकुमार मिश्र, जिला उपाध्यक्ष डॉ. विनोद गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. अमरेन्द्र सिंह, जिला संगठन मंत्री अनुज सिंह, टीएससीटी जिला संयोजक अरविंद यादव, अटेवा जिलाध्यक्ष चंदन सिंह, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय, जिला मंत्री मनीष सिंह सोमवंशी सहित विभिन्न घटक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

श्री लक्ष्मी पूजा महासमिति परिवार ने स्वर्णिमा जायसवाल को किया सम्मानित

स्वच्छ भारत मिशन का ब्राण्ड एम्बेसडकर बनाये जाने पर दी गयी बधाई

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सामाजिक एवं धार्मिक संस्था श्री लक्ष्मी पूजा महासमिति ट्रस्ट जौनपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जायसवाल की पत्नी समाजसेविका स्वर्णिमा जायसवाल को स्वच्छ भारत मिशन की ब्राण्ड एम्बेसडर बनाये जाने पर महासमिति परिवार की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। नगर के ख्वाजगी टोला मोहल्ले में स्थित उनके आवास पर पहुंचे महासमिति के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम के साथ समाजसेविका श्रीमती जायसवाल का अभिनन्दन किया। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये उनके नेतृत्व में जौनपुर नगर का नाम प्रदेश–देश पटल पर रोशन हो, इसके लिये प्रार्थना किया। इस अवसर पर संरक्षक रामजी जायसवाल, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जायसवाल, निर्णायक मण्डल के सदस्य अंजनी प्रजापति, सचिव वैभव वर्मा, मुख्य लेखा परीक्षक कृष्णकान्त विश्वकर्मा, शोभायात्रा प्रभारी राजा अग्रहरि, सत्यम प्रजापति, अभिषेक अग्रहरि सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

महिला दिवस पर विद्या फाउंडेशन द्वारा मां और मांटी कार्यक्रम का आयोजन

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के रोहनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में विद्या फाउंडेशन माधोपुर की तरफ से टिकरी गांव में माँ और माटीऱ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लड़कियों द्वारा बाल विवाह उन्मूलन तथा भ्रूण हत्या की रोकथाम पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं और समाज में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में कुल 128 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं किशोरियों ने भाग लिया। महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सुमंगला, राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस आयोजन में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को प्रमुखता दी गई। बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़कियों ने अपनी आवाज उठाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाई। टिकरी गांव में इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्था के सदस्यों ने महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। इस आयोजन से स्थानीय समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई गई। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई । कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह और भ्रूण हत्या के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया।संस्था ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने का संकल्प लिया। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। टिकरी गांव की लड़कियों ने अपने अभिनय से समाज को महिला अवाम किशोरियों के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिलाओं की समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संस्था ने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना के बारे में जानकारी दिया । कार्यक्रम में सभी उम्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। संस्था ने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम में संस्था की सचिव स्वाति के साथ-साथ प्रियंका, निशा, गणेश, संदीप एवं गोपाल ने भी कार्यक्रम सफल होने में सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया गया।